

रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2004.



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 5 नवम्बर, 2004/14 कार्तिक 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 20 अक्तूबर, 2004

संख्या एल० एल० आर०-बी०(14) 13/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की गमनसूचक अधिसूचना तारीख 9-11-2000 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश, अभियोजन विभाग में संयुक्त निदेशक (वर्ग-I) राजपत्रित के पदों के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग संयुक्त निदेशक (अभियोजन) (वर्ग-I, राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध "क" का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश, अभियोजन विभाग, संयुक्त निदेशक (अभियोजन) (वर्ग-1 राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2004 के उपाबन्ध "क" में,—

(क) स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"07 (सात)"

अभियोजन विभाग	03
पुलिस विभाग	02
प्रवर्तन विभाग	01
सतर्कता विभाग	01

(ख) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"भर्ती की पद्धति सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।

(ग) स्तम्भ संख्या-11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

- (i) उपर्युक्त स्तम्भ संख्या 7 में यथा विहित शैक्षणिक अर्हताएं परिपूर्ण करने वाले उप-निदेशक (अभियोजन) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 3 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो।
- (ii) उपर्युक्त स्तम्भ संख्या 7 में यथा विहित शैक्षणिक अर्हताएं परिपूर्ण करने वाले जिला न्यायवादियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 3 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो :

परन्तु यह कि प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए, सेवाकाल के आधार पर, एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी जिसमें उप-निदेशक (अभियोजन) सामूहिक रूप से जिला न्यायवादी से वरिष्ठ रखे जाएंगे।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिये, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाते के पश्चात् की गई थी। उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन की प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तु की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिये अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व मैनिफेस्ट है, जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मेड पोसिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूलज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अधीन भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूलज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अधीन भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु उपर्युक्त यथा निर्दिष्ट तदर्थ सेवा के गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

(घ) स्तम्भ संख्या 14 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना आवश्यक है।”

आदेश द्वारा,  
जे० पी० नेगी,  
प्रधान सचिव।

[Authoritative English text of this department notification No. LLR-B(14)-13/84, dated 20-10-2004, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## HOME DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th October, 2004

**No. LLR.B(14)-13/84.**—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh, Prosecution Department, Joint Director (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, notified *vide* this department notification of even number dated 9-11-2000, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Prosecution Department, Joint Director (Prosecution) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2004.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure 'A'.*—In Annexure-A to the Himachal Pradesh, Prosecution Department, Joint Director (Prosecution) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2004:—

- (a) for the existing provisions against column No. 2 the following shall be substituted, namely:—

“07 (seven)”

Department of Prosecution	03
Department of Police	02
Department of Enforcement	01
Department of Vigilance (Police)	01

- (b) For the existing title against Column No. 10, the following shall be substituted, namely:—

“Method” of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.

- (c) for the existing provisions against Column No. 11, the following shall be substituted, namely:—

(i) By promotion from amongst the Deputy Director (Prosecution) subject to fulfilling the Educational Qualifications as prescribed in column No. 7 above with three years regular service combined with continuous *ad hoc* service, if any, in the grade.

(ii) By promotion from amongst the District Attorneys subject to fulfilling the educational qualification as prescribed in Col. No. 7 above having 05 years regular service or regular service combined with continuous *ad hoc* service, rendered, if any, in the grade:

Provided that for the purpose of promotion a combined seniority list based on the basis of length of service shall be prepared in which Deputy Director (Prosecution) shall be placed en-bloc senior to District Attorneys.

(1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection. In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

*Explanation.*—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of rule 3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation *ad hoc* service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R & P Rules:

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged;

(d) For the existing provisions against Column No. 11, the following shall be substituted, namely :—

“A candidate for appointment to any service or post must be citizen of India.”

By order,

J. P. NEGI,  
Principal Secretary.

